भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 693

<u>दिनांक 08 दिसंबर 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत-चीन व्यापार

693 **श्री राम नाथ ठाकुरः**
श्री जावेद अली खानः
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान 1 दिसंबर, 2023 तक भारत द्वारा चीन को किए गए निर्यात का भारतीय रुपये में ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान 1 दिसंबर 2023 तक चीन से किए गए आयात का भारतीय रुपये में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान 1 दिसंबर, 2023 तक भारत चीन व्यापार में हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है जिसने इसे वैश्विक विकास में अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी 2010 में 9 वें स्थान से बढ़कर यूके, फ्रांस, इटली और ब्राजील जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 5 वें स्थान पर पहुंच गई है। आईटी, सेवा, विनिर्माण और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने समग्र आर्थिक विस्तार में योगदान दिया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि देखी गई है, जो मोबाइल फोन की पहुंच, इंटरनेट एक्सेस और ई-कॉमर्स के उदय जैसे कारकों से प्रेरित है। भारत में उद्यमशीलता की भावना विकसित हुई है, जिससे कई स्टार्ट-अप और छोटे व्यवसायों का निर्माण हुआ है, नवाचार को बढ़ावा मिला है और नौकरियां सृजित हुई हैं।

पिछले एक दशक में भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के विजन से प्रेरित, सरकार ने कई पहलें की हैं और विभिन्न बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार का विकास व्यय 90.89 लाख करोड़ रुपये था। इसमें अवसंरचना परियोजनाएं, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और अन्य विकास पहलें शामिल हैं।

पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। प्रधान मंत्री जन धन योजना लाखों बैंक रहित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर रही है। आयुष्मान भारत 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर और गरीबों को किफायती आवास प्रदान कर रही है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना इच्छुक उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) हर घर और सार्वजनिक संस्थान को पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति का आश्वासन दे रहा है।

आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ, भारत एक आकांक्षी समाज देख रहा है। शिक्षा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी महिलाओं को उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए सशक्त बना रही है। भारतीय मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण विस्तार देखा है, डिस्पोजेबल

आय बढ़ रही है और उच्च आकांक्षाओं वाले उपभोक्ताओं का एक बड़ा पूल बन रहा है। बढ़ता उपभोक्तावाद आकांक्षा और भौतिक संपत्ति की संस्कृति पैदा कर रहा है।

वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों आदि जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां आयातों पर अत्यधिक निर्भरता है, में सरकार द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की गई हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए, सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

सरकार द्वारा की गई पहलों से आयातों पर निर्भरता में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मोबाइल हैंडसेट का आयात 2014-15 में 48,609 करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 में लगभग 6,685 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर, 2023-24 में, मोबाइल फोन निर्यात अक्टूबर 2023 तक 7.81 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 64,823 करोड़ रुपये) से अधिक हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान 2022-23 में 4.81 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 39,923 करोड़ रुपये) था। इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों और उर्वरकों के आयात में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 36.59%, 11.14% और 20.71% की गिरावट आई है।

सरकार ने अवमानक आयात को रोकने के लिए सख्त गुणवत्ता मानक, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन भी शुरू किया है। सरकार भारतीय व्यवसायों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। घरेलू उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार ने आयात पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है।

इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर आयातों में वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। घटिया आयातों को रोकने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय को अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। सरकार ने घरेलू क्षमताओं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आदि को समर्थन और विस्तार देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए, दिनांक 1 दिसंबर 2023 तक की पूरी अवधि के लिए आधिकारिक व्यापार डेटा उपलब्ध नहीं है। अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 की अवधि के लिए आधिकारिक व्यापार डेटा https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/default.asp. पर उपलब्ध है।

*****